vkj- ,u- vkb- u- UPHIN/2010/32566 Mkd- ith;u- l[;k& SSP/LW/NP-311

अद्भुत समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक हिन्दी साप्ताहिक

हर ख़बर पर पैनी नज़र

o"kZ % 14 vad % 35 y[kuÅ] xq:okj 21 fnlEcj 2023 ls 27 fnlEcj 2023 rd i"B&8 eY; % ,d :i;k

हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि भारत को प्रौद्योगिकी का आयात न करना पड़ेः प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि प्रौद्योगिकी अभूतपूर्व तरीके से जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है औरप्रौद्योगिकी का आयात न करना या इसके लिए दूसरों पर निर्भर न रहना भारत का लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने कहा, भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिभा भंडार है और दुनिया को भरोसा है कि भारत वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए कम लागत वाला गुणवत्तापूर्ण, टिकाऊ व व्यापक समाधान प्रदान कर सकता है। 'स्मार्ट इंडिया हैकथ न' के भव्य समापन के दौरान छात्रों से बातचीत

करते हुए उन्होंने कहा, प्रौद्योगिकी अभूतपूर्व तरीके से हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है, हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि भारत को किसी भी प्रौद्योगिकी का आयात करने की जरूरत न हो या इसके लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। प्रधानमंत्री ने समस्या–समाधान क्षमताओं और जटिल चुनौतियों से निपटने में सरलता के लिए युवा नवप्रवर्तकों की सराहना की। उन्होंने कहा, आज हम समय के उस निर्णायक मोड़ पर हैं, जहां हमारा हर प्रयास अगले हजार साल के भारत की नींव को मजबूत करेगा।

'नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट' तक होगी बेहतरीन रोड, मुख्यमंत्री योगी ने की समीक्षा

लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट 'नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवरश को मेट्रो, हाई स्पीड रैपिड रेल और रोड की सीधी और बेहतरीन कनेक्टिविटी मिलने जा रही है। मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी), उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, एनएचएआई और प्रदेश सरकार के अधिकारियों के साथ एयरपोर्ट की बेहतर कनेक्टिविटी पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जेवर का पूरा क्षेत्र कुछ वर्षों पहले तक अपराध की जद में था। दिन–दहाड़े छिनैती, लूट की घटनाएं होती थी। लेकिन आज इसकी पहचान अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से हो रही है। जेवर एयरपोर्ट के पास ही फिल्म सिटी प्रस्तावित है। अगले कुछ वर्षों में यह एनसीआर का सबसे विकसित क्षेत्र होगा। जेवर एयरपोर्ट, एयर कार्गो का बड़ा हब बनने जा रहा है। अनुमान के मुताबिक जेवर एयरपोर्ट २०२४–२५ में ६५ लाख यात्रियों (प्रतिवर्ष) को सेवायें देगा, जो कि २०४२–४३ तक बढ़कर ०७ करोड़ प्रतिवर्ष होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि जेवर एयरपोर्ट को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय

एयरपोर्ट, नई दिल्ली से कनेक्ट किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए रैपिड रेल और मेट्रो एक बेहतर विकल्प हो सकता है। भारत सरकार, एनसीआरटीसी से इस संबंध में आवश्यक सहयोग परामर्श प्राप्त करते हुए प्रस्ताव तैयार किया जाए। प्रदेश सरकार इसके लिए सभी जरूरी संसाध ान उपलब्ध करायेगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें फरवरी २०२४ में जेवर एयरपोर्ट के रनवे पर ट्रायल लैंडिंग कराना होगा। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए रनवे निर्माण, लाइटिंग आदि की कार्यवाही में तेजी आवश्यक है। रेलवे के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि जेवर एयरपोर्ट को बेहतर कनेक्टिविटी के उद्देश्य से स्थानीय चोला से रुंधी तक लगभग ६८ किलोमीटर की दूरी तक एक नई रेल लाइन पर भी विचार किया जा रहा है। इस संबंध में रेलवे बोर्ड के स्तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। बैठक में मुख्यमंत्री ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अधि ाकारियों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही जेवर एयरपोर्ट की सुरक्षा व जन सुविधा आदि के दृष्टिगत नए थानों, फायर स्टेशन, ड्रेनेज व्यवस्था आदि सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए।

मोदी की गारंटी वाली गाड़ी, हर समस्या के समाधान की गारंटी : केशव मौर्य

लखनऊ। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रत्येक व्यक्ति की हर समस्या के समाधान की यात्रा है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी,हर समस्या के समाधान की गारंटी है। उक्त बातें बुधवार को उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विकास खण्ड बख्शी का तालाब के ग्राम–सोनवा में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा को बतौर मुख्य अतिथि सम्बोधित कर रहे थे। विकसित भारत के संकल्प के साथ, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी, देश व प्रदेश के कोने–कोने में पहुंच रही है। अब आम लोगों ने इस यात्रा की कमान संभाल ली है। हर व्यक्ति इस यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित है। एक जगह जहां पर यात्रा खत्म होती है, वहां से दूसरे गांव, शहर के लोग इस यात्रा की अगुवाई करने लग जाते हैं। मोदी की गारंटी वाली गाड़ीश के सत्कार की भी एक बड़ी स्पर्धा चल रही है। डिप्टी सीएम ने मोदी की गारंटी वाली गाड़ी युवा शक्ति और नारी शक्ति दोनों को ही सशक्त कर रही है। इसका अधिक से अधिक लाभ आप सब लोग उठाएं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाएं। हमारा संकल्प, विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने का एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। इस यात्रा का उद्देश्य वंचितों तक पहुंचना है ,उन कमजोर लोगों तक पहुंचना है,जो विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र हैं लेकिन अभी तक लाभ नहीं उठाया है। इस अवसर पर संजय राय, विधायक योगेश शुक्ला, अरविंद यादव, रवी तिवारी, विजय मौर्य, विमलेश मिश्र, राजीव कश्यप, गौरव सिंह चौहान, अशोक गिरि, प्रमुख जनप्रतिनिधि, मुख्य विकास अधिकारी लखनऊ समेत जिला प्रशासन के अधिकारी भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

प्रधान मंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी? 'इंडिया' बैठक में ममता का प्रस्ताव

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को गठबंधन की चौथी बैठक के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट से इंडिया ब्ल क के उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का नाम प्रस्तावित किया। २०१९ में पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट से प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी की चर्चा ने भी जोर पकड़ लिया, लेकिन जब ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने हाई–प्रोफाइल सीट के लिए अजय राय को मैदान में उतारा तो इस पर विराम लग गया। बैठक के बाद, जब उनसे वाराणसी से प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हम लोग सब कुछ नहीं बता सकते, जो बात हुई है। गठबंधन की चौथी बैठक में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भी इंडिया ब्ल क के सदस्यों से ३१ दिसंबर, २०२३ तक श्सीट–बंटवारेश फ मूले को अंतिम रूप देने का आग्रह किया। सूत्रों ने कहा कि इस बात पर काफी हद तक सहमति बनी कि राज्य स्तर पर सीट–बंटवारे को दिसंबर के अंत तक और अंत में शीर्ष नेतृत्व स्तर पर जनवरी के दूसरे सप्ताह तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान, ममता बनर्जी ने राज्य के लिए लंबित केंद्रीय धन पर चर्चा करने के लिए बुधवार को प्रध ाान मंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। पार्टी के नौ सांसदों के साथ संसद परिसर में बैठक के बाद

मीडिया से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि १५५ केंद्रीय टीमें पहले ही पश्चिम बंगाल का दौरा कर चुकी हैं। राज्य के लिए लंबित मनरेगा निधि के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि श्रमिकों को भुगतान करना संविध ाान के तहत अनिवार्य है। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री) आवास योजना के लिए धन रोक दिया गया है, ग्रामीण विकास योजनाएं बंद कर दी गई हैं, और स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम बंद कर दिया गया है भी बंद कर दिया गया है। हमें वित्त आयोग के तहत धन भी नहीं मिल रहा है।

सावधान हो जाएं, फिर आगया है कोरोना वायरस, ओमीक्रॉन सब-वेरिएंट JN.१ के २१ मामले पाए गए, जानें अब तक की अपडेट

देशभर में अब तक कोविड–१६ सब–वेरिएंट जेएन.१ के २१ मामले सामने आ चुके हैं। गोवा, केरल और महाराष्ट्र में नए कोरोना वायरस वैरिएंट के मामले सामने आए हैं। जबकि गोवा में अब तक कोविड उप–संस्करण JN.१ के १६ मामले सामने आए हैं, केरल और महाराष्ट्र में एक–एक मामले का पता चला है। ओमिक्रॉन वंश का वंशज, JN.१ पिछले कुछ हफ्तों में सबसे तेजी से फैलने वाले वायरस में से एक बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने JN.१ को एक अलग ष्रुचि के प्रकार' के रूप में वर्गीत किया है, लेकिन कहा है कि यह 'कम' वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है। देश भर में कोविड मामलों में बढ़ोतरी के बीच, नीति आयोग के सदस्य

(स्वास्थ्य) डॉ वीके पॉल ने बुधवार को कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पॉल ने कहा कि भारत में वैज्ञानिक समुदाय नए वैरिएंट पर कड़ी नजर रख रहा है। हालाँकि, वीके पॉल ने राज्यों को कोविड की तैयारी बढ़ाने, परीक्षण बढ़ाने और अपनी निगरानी प्रणालियों को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस बीच, केंद्र ने देश भर में कोविड के मामले बढ़ने के कारण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सतर्क रहने को कहा है। सलाह में राज्यों को नियमित आधार पर सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में जिलेवार इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी और गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी के मामलों की निगरानी और रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया।

सम्पादकीय

इंडिया गठबंधन की बैठक

मंगलवार को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक थी। इस बैठक में २५ से ज्यादा दलों के बड़े नेता शामिल हुए थे। इस बैठक के बाद कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन को बनाया गया है। इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव रखा। हालांकि खड़गे ने इससे इनकार किया और कहा कि हमें पीएम बनने के लिए एमपी पर जोर देना होगा। हमें एमपी जीतने होंगे। हालांकि इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा कह दिया जिसको सुनकर सोनिया गांधी सहित तमाम बड़े नेता औचक रह गए। दरअसल, इस बैठक में नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिच पर बैटिंग की। उन्होंने कहा कि देश को भारत के नाम से जाना जाना चाहिए। नीतीश कुमार की मुंह से यह बात सुनकर खुद सोनिया गांधी भी आश्चर्यचकित हो गईं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अधिकारी कामकाज में भारत का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया था। यह विवाद तब शुरू हुआ था जब जीत–२० शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति भवन की तरफ से डिनर के लिए भेजे गए निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट अ फ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट अ फ भारत लिखा गया था। फिलहाल इसी को लेकर नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की बैठक में बड़ी मांग कर दी। नीतीश कुमार ने कहा कि देश को भारत के नाम से जाना जाना चाहिए। नीतीश कुमार की यह बात सभी को हैरान कर दिया। आपको बता दें कि वह नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने विपक्षी एकता को जोड़ने का काम किया। सबसे पहले उन्होंने ही सभी दलों को एक साथ लाने की कोशिश की। पहली बैठक भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में पटना में ही हुई थी। हालांकि नीतीश कुमार कई बार नाराज भी हो चुके हैं। नीतीश कुमार को लेकर उस वक्त भी यह खबर आई थी कि वह गठबंधन का नाम इंडिया रखने को लेकर भी खुश नहीं थे।

उपराष्ट्रपति के अपमान पर भड़के सीएम योगी, विपक्ष को लगाई फटकार

लखनऊ। संसद भवन के परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने पर पूरे देश में विपक्षी नेताओं का विरोध शुरू हो गया है। पीएम मोदी से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और कई अन्य नेताओं ने इस मामले में निराशा जताई है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि विपक्षी सांसदों द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के प्रति व्यवहार असंसदीय, अशोभनीय और अक्षम्य है। सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा, " संसद परिसर में माननीय उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के माननीय सभापति श्री जगदीप धनखड़ जी के प्रति विपक्ष का असंसदीय, अशोभनीय और अक्षम्य आचरण अलोकतांत्रिक होने के साथ ही उनके कुसंस्कारों को भी दर्शाता है। संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के प्रति अहंकार और विद्वेष से परिपूर्ण यह कृत्य अत्यंत ही शर्मनाक है। संसदीय गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले इस कृत्य की मैं घोर निंदा करता हूं''। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री मामले में निशाने पर आने के बाद राहुल गांधी और कल्याण बनर्जी ने सफाई जारी की है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा कभी नहीं था। धनकड़ साहब मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने इसे अपने ऊपर क्यों लिया है। मेरा सवाल यह है कि अगर उन्होंने इसे अपने ऊपर ले लिया है, तो क्या वे राज्यसभा में इस तरह का व्यवहार करते हैं? वहीं, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि सांसद वहां बैठे थे, मैंने उनका वीडियो शूट किया। मेरा वीडियो मेरे फोन पर है। मीडिया इसे दिखा रहा है, किसी ने कुछ नहीं कहा। हमारे १५० सांसदों को (सदन से) बाहर निकाल दिया गया है लेकिन मीडिया में उस पर कोई चर्चा नहीं है।

खत्म हुई सागर शर्मा की रिमांड, अब जेल भेजने की तैयारी में जुटी दिल्ली पुलिस

लखनऊ। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी कर लोकसभा की कार्यवाही के दौरान हंगामा करने वाले सागर शर्मा और उसके साथियों की सात दिनों की रिमांड गुरुवार को खत्म हो जाएगी। अब दिल्ली की स्पेशल सेल सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी में जुटी है। सूत्रों की मानें तो सागर के घर पर दिल्ली से आई स्पेशल टीम ने आरोपी के खिलाफ कई अहम सुबूत जुटा लिए है। इन साक्ष्यों के आधार पर सागर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। फिलहाल, सागर के परिजन अभी भी बेटे को निर्दोष बताते हुए उसकी करतूत को नासमझी की संज्ञा दे रहे हैं। गौरतलब है कि १३ दिसम्बर को संसद हमले की २२वीं बरसी पर लोकसभा की सुरक्षा भेद सदन में घुसे लखनऊ के सागर शर्मा और मैसूर के मनोरंजन डी ने पीले रंग का स्मोक छोड़ दिया था। जिसके बाद आरोपियों ने हंगामा करते हुए नारेबाजी की थी। पकड़े जाने के बाद आरोपियों ने अपने साथी हरियाणा जींद की नीलम आजाद, महाराष्ट्र लातूर के अमोल शिंदे, हरियाणा गुरुग्राम के विक्की शर्मा और बिहार के ललित झा का नाम दिल्ली पुलिस को बताया था। गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया था। हालांकि, मामले की तफ्तीश में जुटी स्पेशल जांच टीम ने साक्ष्य एकत्र करने के लिए सात दिनों के लिए आरोपियों को रिमांड पर लिया था। वहीं, दिल्ली में सागर की गिरफ्तारी के बाद एलआईयू (लोकल इंटेलिजेंस यूनिट) और स्थानीय पुलिस ने सागर के परिजनों से लगातार पूछताछ की और एकत्र किए गए सभी साक्ष्यों को दिल्ली पुलिस सौंप दिया है। इनमें सागर के बंगलुरू कनेक्शन से लेकर फंडिंग की गोपनीय जानकारी भी है। सूत्रों की मानें तो गुरुवार को संसद में हंगामा करने वाले सागर शर्मा की सात दिनों की रिमांड खत्म हो जाएगी। सागर की गिरफ्तारी के बाद परिजन लगातार बेटे को निर्दोष होने की दलीलें दे रहे हैं। कारपेंटर पिता रोशन लाल शर्मा का कहना है कि उन्हें दिल्ली से आई स्पेशल टीम को सभी साक्ष्य मुहैया कराए हैं। बेटे सागर ने सदन में हंगामा किया वह उसकी नासमझी है। उनका कहना है कि मनोरंजन–डी के संपर्क में आने से उनका बेटा भटक गया है। इसमें सागर नहीं बल्कि मनोरंजन दोषी है। हालांकि, सागर के घर वाले उसके बंगलुरू कनेक्शन को भी छिपाते रहे, लेकिन दोस्त के मोबाइल से मिली सागर की दो फोटोग्राफ ने उसके बंगलुरू कनेक्शन की परतें खोल दी हैं। सूत्रों के मुताबिक, रविवार शाम दिल्ली से तहकीकात करने आई स्पेशल टीम ने सागर की निशानदेही पर घर के कमरे, ई–रिक्शा मालिक, बैंक पासबुक, दो डायरियों, किताबों और भारत के नक्शे को जब्त किया था। इसके साथ ही सागर के परिजनों का आधार, पैन, वोटर आईडी समेत उनके हस्ताक्षर लेते हुए कई तरह के साक्ष्य एकत्र किए थे। साक्ष्यों को जुटाने में स्थानीय पुलिस के अलावा लखनऊ की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का अहम योगदान था। सागर के कमरे से मिले सभी साक्ष्यों को दिल्ली स्पेशल पुलिस ने पकड़े गए सभी आरोपियों को दिखाए। साथ ही इनके बारे में सभी से घंटों पूछताछ की गई। फिलहाल, सागर रिमांड खत्म होने और उनके जेल जाने की आंशका पर बुधवार को उसके घर में सन्नाटा पसरा रहा। अब परिजन इस सम्बन्ध में मुंह खोलने से भी कतरा रहे हैं।

यूपीएसआरटीसी की बसों से यात्रा करने वाले पैसेंजरों के लिए अच्छी खबर

लखनऊ। यूपीएसआरटीसी की बसों से यात्रा करने वाले पैसेंजरों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही रोडवेज की बसों से यात्रियों का आवागमन आसान होने के साथ सफर सुहाना,सुरक्षित होगा। रोडवेज की बस बेड़ा में दो हजार नई बीएस–६ डीजल बसें, ३००० एसी इलेक्ट्रिक बसें सम्मिलत होने के साथ ५००० नई इलेक्ट्रिक बसों का अनुबन्ध कर संचालन किया जायेगा। परिवहन यात्रियों की आवागमन बेहतर और हाईटेक सुविधाएं देने के लिए परिवहन निगम तेजी से कार्य कर रहा है। बुधवार को राज्य सड़क परिवहन निगम निदेशक मंडल की २४७ वीं बोर्ड बैठक प्रमुख सचिव परिवहन व परिवहन निगम अध्यक्ष एल. वेंकटेश्वर लू की अध्यक्षता में निगम मुख्यालय में हुई। बोर्ड की बैठक में परिवहन मंत्री की ओर से दिये गये निर्देशों के क्रम में कई अहम निर्णयों को अनुमोदित किया गया। अध्यक्ष परिवहन निगम ने बताया कि परिवहन निगम की डा राम मनोहर लोहिया कार्यशाला कानपुर और केन्द्रीय कार्यशाला कानपुर में पूर्व से संचालित पुरानी बसों का मिनी रिनोवेशन कार्य कराये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया। शासन से मिलने वाली धनराशि में वर्ष २०२४–२५ के आय–व्यय में २००० नई बीएस–६ डीजल बसें, ३००० फुल्ली बिल्ट एसी इलेक्ट्रिक बसों को क्रय कर बस बेडेढ में सम्मिलित किया जाना ५००० नई इलेक्ट्रिक बसों को अनुबन्ध पर लिये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया। अध्यक्ष ने बताया कि परिवहन निगम के ४८ बस स्टेशनों को द्वितीय चरण में पीपीपी पद्धति पर आधुनिक बस टर्मिनल, कॉमर्शियल कॉम्पलैक्स के रूप में विकसित कराने के लिए सहमति प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि परिवहन निगम की बसों, परिचालकों के कार्य के लिए उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से महिला परिचालकों को आबद्ध किये जाने पर सहमति प्रदान किया गया। बोर्ड की बैठक में यूपीएसआरटीसी के प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर, प्रण्ता ऐश्वर्य अपर प्रबन्ध निदेशक, केपी सिंह विशेष सचिव, वीके सोनकिया विशेष सचिव (परिवहन),अभिषेक सिंह विशेष सचिव (सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो), भारतीय प्रबन्ध संस्थान, परिवहन विभाग वित्त विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित रहें।

विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं को दी गई योजना की जानकारी

लखनऊ। मिशन शक्ति नारी स्वावलंबन के तहत बुधवार को विवेकानंद शिक्षा संस्थान पर स्वरोजगार उन्मुख ई–रिक्शा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लखनऊ जिले का केंद्र बनाया गया। वहीं विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं को योजना के बारे में जानकारी दी गई। जिला निर्यात भवन के संतोष कुमार ने बताया कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान कर महिलाओं को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। जहां सरकार स्वरोजगार उन्मुख ई–रिक्शा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर रही है। इसके तहत कई महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। बृहस्पतिवार से दस दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ विवेकानंद शिक्षा संस्थान पर किया जाएगा। वहीं महिलाओं को जानकारी दी गई। कि १.६८ लाख का ई–रिक्शा क्रय करने वाली महिलाओं को विभाग की ओर से २५ प्रतिशत यानी ५० हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। ड्राईविंग लाइसेंस विभाग फ्री में बनवाएगा। इस दौरान जिला निर्यात भवन के संतोष कुमार , अनुराग कुमार, विद्यालय के प्रबंधक डॉ विश्राम प्रजापति, पूजा देवी, शिवानी प्रजापति, प्रिया यादव, सुजाता, समन्वयक अशोक कुमार ने बताया कि प्रशिक्षण केंद्र में और भी महिलाएं भाग लेना चाहते है इस लाभ का जुड़ सके है। रवि कुमार ने अतिथियों और महिलाओं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।

अब दूसरे राज्यों में अपने उत्पाद बेच सकेंगे उत्तर प्रदेश के किसान, मंत्रिमण्डल ने दी मंजूरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल ने राज्य के किसानों को दूसरे राज्यों में अपने उत्पाद बेचने का मौका देने के लिये मंडी नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मंत्रिमण्डल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि अभी तक जो किसान उत्तर प्रदेश से बाहर अपना माल नहीं बेच सकते थे उन्हें अनुमति देने के लिए और खासतौर से उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए मंडी उत्पादन २८ वां संशोधनें२०२३ को अमल में लाने के संबंध में प्रस्ताव आया था जिस पर मंत्रिमण्डल ने आज मुहर लगा दी। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश के किसान अपना माल राज्य के बाहर भी बेच सकेंगे और बाहर के किसान भी अपना माल उत्तर प्रदेश में बेच पाएंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि मंत्रिमण्डल द्वारा लिये गये एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत उत्तर प्रदेश शासन वेतन वृद्धि से एक दिन पहले सेवानिवृत होने वाले न्यायिक अधिकारियों को एक वेतन वृद्धि का लाभ देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गयी। खन्ना ने बताया कि उच्चतम न्यायालय ने १६ मई २०२३ को एक निर्णय दिया था जिसमें कहा गया था कि वेतन वृद्धि से एक दिन पहले जो न्यायिक

अधिकारी सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें पेंशन के उद्देश्य से इसे वेतन वृद्धि को अनुमन्य कर दिया जाए। उनके मुताबिक मंत्रिमण्डल ने एक अन्य निर्णय में देश में मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित गांवों में फोर ४ जी मोबाइल सेवाओं की उपलब्धता से सम्बन्धित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। खन्ना ने बताया कि सरकार की इस योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में ३६१ चिह्नि गांवों को लाने के वास्ते २२६ स्थानों पर नए मोबाइल टावर स्थापित करने के लिए ग्राम सभा की २०० वर्ग मीटर जमीन जिला प्रशासन के माध्यम से भारत संचार निगम लिमिटेड को निशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले घोषणा की थी कि लखनऊ स्थित संजय गांधी परास्नातक आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआई) में एक 'पीडियाट्रिक सेंटर' का निर्माण हो। उनके अनुसार इस सिलसिले में आज मंत्रिमण्डल के समक्ष एक प्रस्ताव आया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। खन्ना ने बताया कि ५७३ बेड के इस अत्याधुनिक 'पेडियाट्रिक' केंद्र का निर्माण दो चरणों में किया जाएगा। इसके निर्माण पर १६६ करोड़ १० लाख ५२००० रुपए का खर्च अनुमानित है। इसे २४ महीने में तैयार किए जाने का प्रस्ताव आया था लेकिन मुख्यमंत्री ने इसे १८ माह में ही पूरा करने के निर्देश दिए हैं। पहले चरण में ३०८ बेड की इकाई तैयार की जाएगी।

यूपी में महंगी नहीं बल्कि सस्ती होगी शराब, योगी सरकार की नई आबकारी नीति का गणित

लखनऊ। योगी सरकार की नई आबकारी नीति लागू होने के बाद प्रदेश में ना सिर्फ कंट्री मेड शराब की कीमतों में कमी आएगी, बल्कि सरकार के खजाने को भी समृद्ध किया जा सकेगा। प्रदेश के आबकारी आयुक्त सेंथिल पांडियन सी ने नई आबकारी नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य में कंट्री मेड शराब की विभिन्न कैटेगरीज को संक्षिप्त करते हुए इन्हें अब केवल चार हिस्सों में बांटा गया है। पहले ये नौ श्रेणियों में होती थीं और इनके दाम भी अलग अलग होते थे। उन्होंने बताया कि शराब की कीमतों में कमी लाने का सबसे बड़ा कारण यूपी में ग्रेन अल्कोहल को बढ़ावा देने की नीति है। इससे प्रदेश की दूसरे राज्यों पर निर्भरता खत्म हुई है और राजस्व को भी फायदा मिल रहा है। आबकारी आयुक्त के अनुसार सरकार शीरे वाली शराब की जगह ग्रेन (अनाज) वाली शराब को बढ़ावा दे रही है। दुनियाभर में ग्रेन अल्कोहल को सबसे ज्यादा क्वालिटी युक्त माना जाता है। पहले हमें ग्रेन अल्कोहल को पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों से इम्पोर्ट करना पड़ता था, वहीं अब इनका निर्माण प्रदेश में ही हो रहा है। ऐसे में इम्पोर्ट ड्यूटी तो बच ही रही है, जीएसटी में भी कमी आई है, साथ ही लाइसेंस फीस का भी २५४ रुपए प्रति बल्क लीटर निर्धारण करने से सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। इसके अलावा मिनिमम गारंटी कोटा और मिनिमम गारंटी रेवेन्यू में १० प्रतिशत का इजाफा करने से २०२४–२५ में ५० हजार करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य है। बावजूद इसके शराब के रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, बल्कि ग्रेन अल्कोहल और यूपीएमल की शराब की ४२.८ डिग्री वाली मदिरा पहले जहां ६० रुपए की

मिलती थी उसके दाम घटकर ८५ रुपए हो जाएंगे। वहीं यूपीएमएल की शराब में ३६ डिग्री वाली मदिरा नई श्रेणी के रूप में जोड़ी गई है, जिसकी कीमत को ७५ रुपए रखी गई है। इसके अलावा शीरे वाली शराब को भी केवल दो कैटेगरी में रखा गया है। इसमें २५ डिग्री की कीमत ५० रुपए और ३६ डिग्री की कीमत ७० रुपए रखी गयी है। इनकी दरों में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके साथ ही पहली बार यूपीएमएल की शराबों को ग्लास के साथ साथ टेट्रा पैक में भी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि राजस्व वृद्धि के लिए पहली बार हम फ्रेंचाइजी फी भी लेकर आए हैं, जिससे दुनियाभर के टॉप ब्रांड यूपी की डिस्टलरीज के साथ फ्रेंचाइजी स्थापित कर सकें। आबकारी आयुक्त के अनुसार प्रदेश में अगर किसी ब्रांड की डिमांड बढ़ती है एवं आसवानियों की कैपेसिटी खत्म हो गई हो तब एक साल के लिए उन्हें दोगुना लाइसेंस फीस के साथ बाहर से मदिरा खरीद कर बॉटलिंग बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। इससे प्रदेश का राजस्व तो बढ़ेगा ही, बॉटलर्स/आस्वकों को भी नई डिस्टलरी लगाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। बियर एक्सपोर्ट फीस को भी ५० पैसे प्रतिलीटर कम किया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश को बियर एक्सपोर्ट के मामले में और मजबूत स्थिति में लाया जा सके। इसके साथ ही प्रचलित व्यवस्था के प्राविधानों में दुरुपयोग रोकने के भी तमाम प्रयास किये गये हैं। इनमें बीयर की दुकानों के पास १०० स्क्वायर फीट के स्थान को परमिट रूम के तौर पर डेवलप किया जा सकेगा। इसकी परमिशन लेने ५ हजार रुपए सालाना शुल्क होगी। परमिट रूम का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ठंडी बियर को बियर की दुकानों के पास ही पीने की सुविधा मिल सकेगी। इससे सड़क पर या कहीं कोने में अवैध रूप से बीयर पीने से होने वाली असुविधा और कई बार सड़क पर छेड़खानी, मारपीट जैसे अपराधों और अन्य असुविधाजनक स्थिति से बचा जा सकेगा।

भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर को

लखनऊ। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उनके पैतृक गांव बटेश्वर में हुए विकास कार्य और सांस्कृतिक संकुल केंद्र व पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का लोकार्पण २५ दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह नौ बजे बटेश्वर पहुंचेंगे। यहां पर सीएम योगी १०० करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित दौरे को लेकर जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर ने बटेश्वर का दौरा किया। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मस्थली बटेश्वर को देखने के लिए देश– विदेश से पर्यटक आएं और यहां धार्मिक पर्यटक का आनंद लें। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास की गंगा बहा दी है।बटेश्वर के विकास के लिए १०० करोड़ से अधिक की परियोजनाएं बनाई है, जिसका शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। अब बटेश्वर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मस्थली और धार्मिक पर्यटन के लिए देश– विदेश में पहचाना जाएगा। मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को देखते हुए जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी और पुलिस कमिश्नर डॉ. प्रीतिंदर सिंह ने बटेश्वर का दौरा किया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल को देखा और वहां पर तैयारियों को पूरा करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी ने प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल, पार्किंग व्यवस्था, सड़क व मुख्यमंत्री के आगमन के संभावित मार्ग, बटेश्वर मंदिर व सांस्ंेतिक संकुल परिसर का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने नालों की साफ सफाई, वॉल पेंटिंग, सड़क मरम्मत आदि विकास कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के संबंधित को कड़े दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बटेश्वर का भी निरीक्षण किया जहां उचित साफ– सफाई न मिलने पर संबंधित को कड़ी फटकार लगाई तथा नियमित साफ सफाई कराने के निर्देश दिए। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का संभावित आगमन २५ दिसंबर को बटेश्वर में प्रस्तावित है। यहां पर मुख्यमंत्री

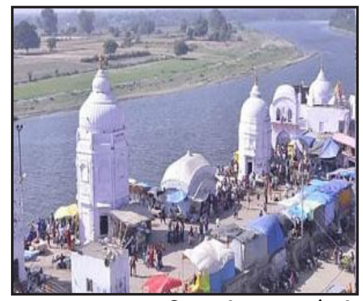

द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी सांस्कृतिक संकुल केन्द्र के भवन का लोकार्पण तथा उसी परिसर में अटल जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। साथ ही विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। यह सभी परियोजनाएं संस्कृति व पर्यटन विभाग की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आगरा व मथुरा के लिए हेलीपोर्ट सेवाओं के अंतर्गत हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ भी करेंगे। यहां पर सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे तथा तीन दिवसीय अटल कृषि मेला तथा कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। वहीं लाभार्थियों को सम्मानित करेंगे। बता दें कि यमुना नदी के किनारे १०८ मंदिरों की श्रृंखला हैं, जो अपनी धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्ता का गुणगान करते हैं। बटेश्वर मंदिरों के घाटों का निर्माण मंदिरों पर जीर्णोद्धार व पार्क आदि का एकीत विकास हुआ है। दर्शनार्थियों की सुविधा हेतु पर्यटन की दृष्टि से जहां पर सर्वाधिक विकास किया है, इससे पर्यटकों की संख्या बढेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

साइबर अपराधियों ने तीन लोगों के बैंक खातों से 3.93 लाख पार किये

लखनऊ। साइबर अपराधियों ने तीन लोगों को झांसे में लेकर उनके बैंक खातों से रुपये पार कर दिये। पीड़ितों ने विभूतिखंड और सरोजनीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी है। पुलिस आरोपी की पहचान का प्रयास कर रही है। विभूतिखंड के रोहतास प्लूमेरिया निवासी मो. हफीजुर रहमान ने बताया कि उनका आई सीआ ईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है। शुक्रवार को उनके क्रेडिट कार्ड का क्लोन बनाकर खाते से पांच बार में ६६,३२८ रुपये निकाल लिये गये। मोबाइल पर बैंक का मैसेज आने पर ठगी का पता चला। उन्होंने विभूतिखंड थाने में आईटी एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई है। उधर, गोमतीनगर के विभव खंड निवासी राहुल उपाध्याय ने बताया कि उनका खाता एसबीआई बैंक में है। कुछ दिन पहले अनजान नंबर से काल आयी, खुद को बैंक कर्मी बताते हुये उधर से केवाईसी अपडेट कराने का झांसा देकर बैंक डिटेल हासिल की। इसके बाद लिंक भेजकर खाते से ३३,३७६ रुपये पार कर दिये। एक अन्य मामले में राजाजीपुरम ई–ब्लाक निवासी मनीष कुमार साइबर ठगी का शिकार हो गये। बताया कि कुछ दिन पहले व्हाट्सअप पर पार्ट टाइम जॉब का मैसेज आया था। जालसाज ने टास्क पूरा करने पर रुपये देने का झांसा दिया। आरोपी ने टास्क के नाम पर २.६० लाख रुपये जमा करा लिए। इसके बाद नंबर बंद कर लिया। पीड़ित ने सरोजनीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी है।

सीवर सफाई के दौरान हो रही मजदूरों की मौत पर योगी सरकार गंभीर

लखनऊ। सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई जैसे खतरनाक कार्य में लगे लोगों की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार गंभीर है। इसके लेकर सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का प्रदेश में पूर्णतः पालन किया जा रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय निदेशालय ने सभी नगर आयुक्तों, जलकल एवं जल संस्थान के महाप्रबंधकों एवं समस्त अधिशासी अधिकारियों को पत्र लिखकर सीवर एवं सेप्टिक टैंकों की सफाई में विभाग की ओर से पहले जारी की जा चुकी एसओपी का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि खतरनाक सफाई के दौरान अत्याधुनिक सफाई उपकरणो एवं आवश्यक उपस्करों का उपयोग किए बिना सफाई का कार्य नहीं किया जाएगा। निकाय स्तर पर सीवर, सेप्टिक टैंकों की सफाई के दौरान किसी भी व्यक्ति से मैनुअल सफाई कार्य नहीं कराया जाना है एवं सफाई कर्मचारियों को समय–समय पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, ताकि किसी प्रकार की जनहानि न हो। उल्लेखनीय है कि २० अक्टूबर २०२३ को सुप्रीम कोर्ट ने सीवर एवं सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले कर्मियों की सुरक्षा के संबंध में राज्यों को कड़ा आदेश दिया था। इसमें मैनुअल सफाई नहीं कराने के अलावा दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में ३० लाख रुपए के हर्जाने की भी बात कही गई थी। स्थानीय निकाय निदेशालय के निदेशक ड . नितिन बंसल द्वारा जारी आदेश के अनुसार सीवर, सेप्टिक टैंकों की सफाई को लेकर पहले भी विभाग द्वारा सभी निकायों को समय–समय पर एसओपी जारी की जाती रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों

के क्रम में सभी नगर आयुक्तों, अधिशासी अधिकारियों और जल संस्थान के महाप्रबंधकों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने निकाय स्तर पर पूर्व में जारी एसओपी के समस्त बिंदुओं का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराएं तथा इस संबंध में संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को भी निर्देशित करने का कष्ट करें। पूर्व में जारी एसओपी के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को सीवर सफाई के लिए सीवर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। अतः सीवर सफाई के लिए बिना समुचित सुरक्षा उपायों के सीवर में प्रवेश प्रतिबंधित है। सेप्टिक टैंक, सीवर की नियमित सफाई तथा अनुरक्षण, अधिकतम यंत्रीकरण, निर्धारित नियमों और मानक संचालन प्रक्रिया एवं सुरक्षा उपकरणों के साथ सुनिश्चित किया जाए. असुरक्षित सफाई कराना कानूनी अपराध है। एसओपी के अनुसार, सभी निकायों में सीवर लाइन सफाई एवं सेप्टिक टैंक, पिट की सफाई के लिए आईईसी गतिविधियां संचालित की जाएंगी, जिससे आमजन एवं सफाई कर्मचारियों को जागरूक किया जा सके। साथ ही यह संदेश दिया जाएगा कि सीवर सफाई आवश्यक सुरक्षा उपकरणों एवं प्रशिक्षित कामगारों जिसके पास वैध आईडी कार्ड हो, से ही एसओपी के अनुसार कराई जाए। इसके अतिरिक्त सुपरवाइजर पर्याप्त मशीनरी एवं सुरक्षा उपकरणों के साथ साइट पर उपस्थित रहे। सीवर सफाई का कार्य उस अवधि में किया जाए जब सीवर में सीवर की मात्रा न्यूनतम हो। इसके अलावा एसओपी में पंजीत संस्थाओं, ठेकेदारों, फर्मों से कार्य करवाए जाने पर स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी तय की गई है जबकि स्थानीय निकाय द्वारा सफाई प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने पर भी जिम्मेदारियां तय की गई हैं।

जब किसानों को नक्सलवादी और उग्रवादी बताया गया तो क्या यह अपमान नहीं था : सुरजेवाला

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी के 'मिमिक्री' किए जाने से जुड़े विवाद की पृष्ठभूमि में बुधवार को कहा कि जब आंदोलनकारी किसानों को उग्रवादी तथा नक्सलवादी कहा गया तो क्या यह किसानों का अपमान नहीं था। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद परिसर में उनकी, तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद द्वारा नकल उतारे जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए उच्च सदन में कहा कि संसद परिसर में उनकी नकल उतारकर किसान समाज और उनकी जाति (जाट) का अपमान किया गया है। राज्यसभा सदस्य सुरजेवाला ने एक बयान में कहा, ''जब किसान आंदोलन में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब समेत देश के अन्य राज्यों के किसानों को मोदी सरकार के लोग उग्रवादी, नक्सलवादी और अराजक तत्व बता रहे थे तो क्या ये किसानों का अपमान नहीं था? जब किसान आंदोलन में ७०० किसान शहीद हो गए तब संसद में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)–राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का एक भी सांसद खड़ा नहीं हुआ था तो क्या ये किसानों का अपमान नहीं था?'' उन्होंने कहा, ''जब किसानों को एक भाजपाई ने गाड़ी के नीचे कुचल कर मार डाला, जब दिल्ली के दरवाजे पर उनके रास्ते में कीलें लगा दी गई तो क्या ये किसानों का अपमान नहीं था? तब किसानों का अपमान क्यों दिखाई नहीं दिया?'' सुरजेवाला ने कहा, ''जब किसानों की पहलवान बेटियों का भाजपा के सांसद द्वारा यौन शोषण किया गया, जब वे संसद के दरवाजे पर न्याय के लिए सिसकती रही, जब उन्हें भाजपा सरकार की पुलिस द्वारा जूतों के नीचे रौंदा गया, जब उन्हे संसद के बाहर जंतर–मंतर पर सड़कों पर घसीटा गया तो जब किसानों का अपमान नहीं हुआ?'' उन्होंने कहा, ''जब फौज की सेवा करने वाले किसानों के भाई, बेटे और महिलाएं देश की संसद के बाहर "वन रैंक, वन पेंशन" की गुहार लगा रहे थे तो १५ अगस्त से एक दिन पहले, १४ अगस्त की शाम को उन्हें जंतर–मंतर की सड़कों पर घसीट कर अपमानित किया गया, गिरफ्तार किया गया तो किसानों की बेइज्जती नहीं हुई? उन्होंने कहा कि पद की गरिमा जाति से नहीं, कर्तव्य बोध से होती है। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा, ''जब संविधान पर सरकार ही आक्रमण कर रही तो उसका विरोध करना सच्ची देशभक्ति है।

अदालत ने भगोड़े स्वयंभू उपदेशक के आश्रम में रह रही महिला को पेश होने का निर्देश दिया

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बलात्कार के आरोपी एवं फरार स्वयंभू आध्यात्मिक उपदेशक वीरेंद्र देव दीक्षित के राष्ट्रीय राजधानी स्थित आश्रम में रह रही उस महिला से अदालत में पेश होने को कहा है, जिसके बुजुर्ग माता–पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी ''उच्च शिक्षा प्राप्त'' बेटी को गुमराह किया जा रहा है। माता–पिता ने उनकी सहमति के बिना रोहिणी के आध्यात्मिक विश्व विद्यालय में रह रही अपनी बेटी के साथ बातचीत का अवसर मुहैया कराने का अदालत से आग्रह किया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने कहा कि महिला वयस्क है और उसे अपने माता–पिता से मिलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। पीठ ने कहा, ''बेटी बालिग है। हम उसे मजबूर नहीं कर सकते। उसकी अपनी समझ है।'' याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि आश्रम में रह रहे लोगों की स्थिति के संबंध में रोहिणी के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अगुवाई वाली एक समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर उनकी बेटी का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने के निर्देश दिए जाएं। मामले में नियुक्त न्याय मित्र ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की बेटी वयस्क है जो उच्च न्यायालय के समक्ष पहले ही बयान दे चुकी है कि वह स्वेच्छा से आश्रम में रह रही है और अपने माता–पिता से मिलना नहीं चाहती। न्याय मित्र ने कहा कि बेटी की आस्था भले ही कुछ भी हो, यदि उसकी दिमागी स्थिति दुरुस्त है, तो उसकी इच्छा के खिलाफ उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ताओं की बेटी के वकील ने कहा कि वह ३८ वर्षीय महिला है और वह अपने माता–पिता से मिलने की इच्छुक नहीं है और मनोचिकित्सकों ने २०१८ में ही उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कर लिया था। न्याय मित्र ने सुझाव दिया कि अदालत कोई आदेश पारित करने से पहले महिला के साथ संवाद कर सकती है। इसके बाद अदालत ने कहा, ''तदनुसार, प्रतिवादी संख्या चार (बेटी) को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। मामले को जनवरी के लिए सूचीबद्ध किया जाए।'' याचिकाकर्ताओं ने आश्रम की ''हिरासत'' से अपनी बेटी की ''रिहाई'' के लिए २०२० में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने वकील श्रवण कुमार के माध्यम से दायर अपनी याचिका में कहा कि आश्रम ''बलात्कार और अन्य गंभीर अपराधों के ऐसे आरोपी द्वारा चलाया जा रहा है'' जो फरार है और उनकी बेटी को एक मनोवैज्ञानिक विकार एवं पीठ में तीव्र दर्द की परेशानी के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों से उपचार कराने की आवश्यकता है। इस मामले के अलावा उच्च न्यायालय गैर सरकारी संगठन 'फाउंडेशन फ र सोशल एम्प वरमेंट' की २०१७ में दाखिल याचिका पर भी सुनवाई कर रहा है। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि दीक्षित के रोहिणी स्थित 'आध्यात्मिक विश्वविद्यालय' में अनेक नाबालिगों लड़कियों और महिलाओं को अवैध तरीके से बंधक बनाकर रखा गया है और उन्हें उनके माता–पिता से मिलने नहीं दिया जाता।

एयर इंडिया के एक विमान के एक इंजन में आग लगने की चेतावनी का संकेत मिला

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी से मुंबई के लिए उड़ान भरने वाले एयर इंडिया के एक विमान के एक इंजन में आग लगने की चेतावनी का संकेत मिला था। एयर इंडिया ने बुधवार को यह जानकारी दी। मंगलवार को यहां से उड़ान भरने वाले विमान 'एआई ८१४' का संचालन ए३२० विमान से किया गया। एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने बुधवार को एक बयान में कहा कि विमान सुरक्षित उतार लिया गया और निरीक्षण करने पर आग या धुएं का कोई निशान नहीं मिला। प्रवक्ता ने कहा, "१६ दिसंबर २०२३ को दिल्ली से मुंबई के लिए उड़ान भरने वाले एआई८१४ के एक इंजन में आग लगने की चेतावनी का संकेत देखा। एहतियात के तौर पर, आपातकाल स्थिति की घोषणा करके हवाई यातायात नियंत्रण को सूचित किया गया।

नाबालिग लड़की से सामूहिक बलात्कार के आरोप में पांच लोगों पर मुकदमा

मऊ। मऊ जिले के रानीपुर क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक महेश सिंह अत्री ने बृहस्पतिवार को बताया कि बुधवार की शाम रानीपुर थाने पर १४ वर्षीय एक लड़की के साथ दुष्कर्म के संबंध में एक तहरीर प्राप्त हुई है। इस मामले में रात को पांच व्यक्तियों के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि घटना मंगलवार देर रात की बताई जा रही है। तहरीर के मुताबिक, जब किशोरी घर से अकेले शौच के लिए निकली थी तब अभियुक्तों ने घटना को अंजाम दिया। घटना का वीडियो बनाकर आरोपियों ने पीड़ित को धमकाया कि किसी को इस बारे में बताने पर वे वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देंगे। उन्होंने उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। अत्री ने बताया कि घटना का एक वीडियो मिला है जिसे देखने से प्रथम ष्टया ऐसा नहीं लगता कि पीड़िता के साथ जोर–जबरदस्ती हुई। उन्होंने बताया कि पीड़िता नाबालिग है इसलिए यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून (पोक्सो एक्ट) और भारतीय दंड विधान की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश के लिए चार टीमें गठित की गई है, जो संबंधित स्थानों पर छापेमारी कर रही हैं।

नए भारत का नया कानूनः PM मोदी मिटा रहे गुलामी के निशान, मॉब लिंचिंग, लव जिहाद, प्रॉपर्टी जब्त... नए कानून में कितनी सजा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल १५ अगस्त में पांच प्रण दिए थे। उसमें उन्होंने कहा था कि गुलामी की जितनी भी निशानियां हैं उससे मुक्ति पाना सबसे पहले काम है। गुलामी की सबसे बड़ी निशानी होने का ठप्पा आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंश एक्ट पर था। १८३०, १८५६, १८७२ उस दौरान इन सब चीजों को लाया गया और हम अब तक ढो रहे थे। आईपीसी का असल में नाम आयरिश पीनल कोड था। ये बात तो सभी जानते हैं कि अंग्रेज हिन्दुस्तान की जनता को सहूलियत देने के लिए कानून नहीं बनाते थे। किस तरह से हम सभी को सिस्टम के प्रति एक गुलाम की तरह ट्रीट करे। संविधान तो तैयार कर लिया गया लेकिन अपराध और अपराधियों को पकड़ने का सिस्टम अंग्रेज के जमाने से था। एक शख्स था थोमस बैबिंगटन मैकाले ये भारत तो आया था अंग्रेजी की पढ़ाई करने लेकिन उसके बाद इसी भारत में अगर किसी ने देशद्रोह का कानून ड्राफ्ट किया तो वो लार्ड मैकाले ही था। लेकिन भारत के गृह मंत्री ने ऐसा काम किया है। गुलामी की जंजीरों से पूरे सिस्टम को आजादी दी है। शाह ने संसद को यह भी बताया कि केंद्र म ब लिंचिंग के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान लागू है। जब पांच या अधिक व्यक्तियों का एक समूह एक साथ मिलकर नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य आधार पर हत्या करता है तो ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्य को मृत्युदंड या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। नए प्रावधान में कहा गया है कि आजीवन कारावास या सात साल से कम की कैद नहीं होगी और जुर्माना भी देना होगा। इस विधेयक में महिलाओं के खिलाफ अपराध और उनके सामने आने वाली कई सामाजिक समस्याओं का समाधान किया गया है। प्रस्तावित कानून में पहचान छिपाकर किसी महिला से शादी करने के अलावा रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे के तहत महिलाओं के साथ पहली बार संबंधा बनाना अपराध होगा। यौन हिंसा के मामलों में बयान महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट ही करेगी। गैंगरेप के मामलों में २० साल की सजा या आजीवन कारावास की सजा। लोकसभा ने बुधवार को तीन संशोधित आपराधिक कानून विधेयक पारित किए, जिनका उद्देश्य देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करना और भारतीय सोच पर आधारित न्याय प्रणाली स्थापित करना है। विधेयक में भारतीय न्याय संहिता भारतीय दंड संहिता को बदलने का प्रस्ताव करती है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आपराधिक प्रक्रिया संहिता को बदलने का प्रयास करती है और भारतीय साक्ष्य संहिता भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेती है। लोकसभा में विधेयकों को पेश करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मौजूदा आपराधिक कानून न्याय प्रदान करने के बजाय दंडित करने के इरादे से औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाते हैं। अमित शाह ने कहा कि भारतीय दंड संहिता का उद्देश्य दंड देना था, न्याय नहींय इसके स्थान पर भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, २०२३ सदन से पारित होने के बाद देश में लागू होगी। गृह मंत्री ने कहा कि नए आपराधिक कानून विधेयक संविधान की भावना के अनुरूप हैं। विधेयकों को शुरू में संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया गया था लेकिन बाद में वापस ले लिया गया। अमित शाह ने पिछले हफ्ते लोकसभा में संशोधित बिल दोबारा पेश किया। लोकसभा से पास होने के बाद अब बिल को राज्यसभा में २१ नवंबर को पेश किया जाएगा।

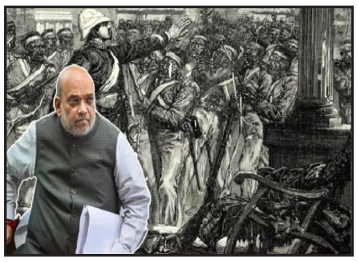

अब लखनऊ का नाम! लक्ष्मणपुरी करने की है तैयारी

लखनऊ। लखनऊ का नाम अब बदल सकता है! नगर निगम की ओर से इसका नाम बदले जाने का प्रस्ताव पास करने की तैयारी है। इसके बाद यह प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा, फिर नाम बदले जाने की घोषणा राशन की ओर से की जा सकती है। बता दे कि यूपी में योगी सरकार के पहले कार्यकाल से ही इस बात की चर्चा चल रही है की लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मण पुरी किया जाए। इससे पहले पूर्व मेयर सयुंक्ता भाटिया ने भी इस मुद्दे को उठाया था। योगी सरकार इससे पहले भी कई जिलों का नाम बदल चुकी है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मीडिया में बयान देकर यह बात कह चुके हैं कि अगर कहीं पर इतिहास से छेड़छाड़ की गई है तो उसे बिल्कुल बदला जाना चाहिए। हालांकि यूपी में जिलों का नाम परिवर्तन करने का सिलसिला तत्कालीन मायावती सरकार ने शुरू किया था। इसके बाद अखिलेश यादव ने भी कुछ जिले के नाम बदले थे। और योगी सरकार में भी नाम बदले जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करना हो या फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या करना। योगी को नाम बदलने के अपने इस फॉर्मूले का काफी फायदा मिला है और उनके प्रस्तावों को केंद्र और जनता की तरफ से काफी स्वीकार्यता भी मिली है। हालांकि, अब जिस शहर के नाम बदलने की चर्चा सबसे ज्यादा है, उनमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सबसे ऊपर था जो अभी तक नहीं बदल गया था। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि यह नाम बदल जाएगा और लखनऊ का नाम लक्ष्मण पूरी हो

जाएगा। मई २०२२ मे भी योगी आदित्यनाथ ने स्वयं में ट्वीट करके लखनऊ का नाम बदले जाने का जोड़ दिया था तब उसे समय मीडिया डिबेट में काफी बहस भी छिड़ी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का या ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लखनऊ आने था। जिसमे लिखा था की शेषावतार भगवान श्री लक्ष्मण जी की पावन नगरी लखनऊ में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन...इस ट्वीट में उन्होंने पीएम मोदी के साथ अपनी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की एक फोटो भी पोस्ट की थी। योगी के इस ट्वीट के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया तब से यह चर्चा टूल पड़े हुए हैं और कई बार लखनऊ का नाम लक्ष्मण पुरी किए जाने को लेकर चर्चा हो चुकी है।

ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति ने कहा–कोई भी चीज तश्तरी में सजाकर नहीं देगी, कानूनी लड़ाई लड़ेगी

वाराणसी। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की प्रबंधन समिति अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर–ज्ञानवापी भूमि स्वामित्व मामले में वर्ष १६६१ के सिविल मुकदमे को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज किये जाने के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने के स्पष्ट संकेत देते हुए कहा कि वह कोई भी चीज तश्तरी में सजाकर नहीं देगी और आखिरी सांस तक कानूनी लड़ाई लड़ेगी। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के संयुक्त सचिव सैयद मुहम्मद यासीन ने पीटीआई से फोन पर बातचीत में उच्च न्यायालय के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दिये जाने की सम्भावना के सवाल पर कहा, हमारे पास आदेश आ गया है लेकिन अभी हम उसका अध्ययन करेंगे और कमेटी की बैठक में तय करेंगे कि आगे हमें क्या करना है। हम बुधवार शाम तक किसी निर्णय पर पहुंच जाएंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा, हम यह मानकर चल रहे हैं कि यह फैसला हुआ है, इंसाफ नहीं हुआ है। मगर इतना समझ लीजिये कि हम तश्तरी में सजाकर नहीं देने जा रहे हैं। हम आखिरी दम तक आखिरी सांस तक कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर–ज्ञानवापी भूमि स्वामित्व मामले में १६६१ के सिविल मुकदमे को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और कहा कि निचली अदालत के समक्ष मुकदमा कायम रखने योग्य है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अपने फैसले में कहा कि वर्ष १६६१ में जिला अदालत के समक्ष दायर मुकदमा कायम रखने योग्य है और यह पूजा स्थल अधिनियमें १६६१ के तहत वर्जित नहीं है। अदालत ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह मुकदमे पर तेजी से सुनवाई करे और छह महीने के अंदर फैसला करे। न्यायालय ने आगे कहा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को निचली अदालत के समक्ष अपनी रिपोर्ट जमा करनी है। अगर जरूरी हुआ तो निचली अदालत एएसआई को आगे के सर्वेक्षण के लिए निर्देशित कर सकती है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा करने का अधिकार मांगने वालेकुछ हिंदू उपासकों ने यह मुकदमा दायर किया था। वाराणसी अदालत के समक्ष लंबित इस मुकदमे में ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर एक प्राचीन मंदिर को बहाल करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि मस्जिद दरअसल मंदिर का हिस्सा है।

पीएम मोदी ने हामिद अंसारी का किया था अपमान, जयराम रमेश ने शेयर किया पुराना वीडियो

नई दिल्ली। जयराम रमेश ने कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी का अपमान करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह बात कही जबकि बीजेपी ने विपक्षी दलों पर मौजूदा राज्यसभा सभापति और

उपसभापति जगदीप धनखड़ का अपमान करने का आरोप लगाया। रमेश ने कहा कि १० अगस्त २०१७ को हामिद अंसारी की विदाई का दिन था। अंसारी दस साल के लंबे कार्यकाल के बाद उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति पद से सेवानिवृत्त हो रहे थे। तब यह सबसे चौंकाने वाली बात थी कि प्रधानमंत्री ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित राजनयिकों में से एक अंसारी का मजाक उड़ाया, उनकी पहचान को उनके धर्म तक सीमित कर दिया और वास्तव में आरोप लगाया कि उनकी संपूर्ण व्यावसायिक और राजनीतिक उपलब्धियाँ उनकी धार्मिक पहचान के कारण थीं। पीएम ने शाम को संसद पुस्तकालय सभागार में विदाई समारोह में भी लगभग यही दोहराया। संवैधानिक अधिकारियों के अपमान की बात करने वाले ऐसे तुच्छ प्रधानमंत्री और उनके ढोल बजाने वाले निंष्ट प्रकार के पाखंडी और अवसरवादी हैं। यह संसद से १४४ सांसदों के अलोकतांत्रिक निलंबन और १३ दिसंबर को लोकसभा में चौंकाने वाले सुरक्षा उल्लंघन से ध्यान भटकाने के अलावा और कुछ नहीं है। रमेश ने कहा कि ऐसे प्रधानमंत्री और उनके समर्थक अब संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने की बात कर रहे हैं, यह उनकी अवसरवादिता को दर्शाता है। संसद से १४४ सांसदों के अलोकतांत्रिक निलंबन और १३ दिसंबर को लोकसभा में चौंकाने वाले सुरक्षा उल्लंघन से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा ने इस मुद्दे को बढ़ा–चढ़ाकर पेश किया।

अगर भाजपाई शराब को अच्छा समझते हैं, तो इसे अपने कार्यालय से बेचें : अखिलेश यादव

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और क्रूज में शराब की बिक्री की अनुमति देने को लेकर बुधवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि शराब और अपराध के बीच गहरा संबंध है और उन्होंने भाजपा को सुझाव दिया कि अगर वे इसे अच्छा समझते हैं तो इसे अपने कार्यालयों से बेचें। उन्होंने कहा कि भाजपाई इस तरह सार्वजनिक स्थलों को अराजकता और अपराध् ा का केंद्र न बनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को २०२४–२५ के लिए अपनी आबकारी नीति को मंजूरी दे दी, जिसमें हवाई अड्डे, मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशन से शराब की बिक्री के प्रावधान की अनुमति है। यादव ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' (पूर्व ट्विटर) पर अपनी एक पोस्ट में कहा, ''उप्र भाजपा सरकार के पास एक ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए क्या

यही एक रास्ता बचा है कि शराब रेलवे, मेट्रो स्टेशन व क्रूज पर बेची जाए।'' उन्होंने कहा, ''इसका मतलब ये हुआ कि लाखों–करोड़ों के निवेश के जो भी दावे किए गए थे, वो सब झूठे साबित हुए हैं, तभी तो सरकार ऐसे अनैतिक रास्तों को अपना रही है। आज शराब बिक कर रही है कल को दूसरे और भी मादक पदार्थ सार्वजनिक जगहों पर बेचे जाएंगे।'' यादव ने कहा, ''अगर भाजपाई समझते हैं कि शराबखोरी इतनी ही अच्छी है तो अपने कार्यालयों से बेचें, सार्वजनिक स्थलों को अराजकता और अपराध् ा का केंद्र न बनाएं।'' पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ''सरकार ऐसे फैसलों से घर–परिवार को बर्बाद न करे। महिलाएं और बच्चे जानते हैं कि शराब किस प्रकार घरेलू हिंसा से लेकर सार्वजनिक हिंसा का कारण बनती है और युवाओं के लिए घातक साबित होती है। इस फैसले के विरोध में उप्र की महिलाएं, परिवारवाले और युवा, भाजपा कोसत्ता से हटाने का फैसला करेंगे।'' सपा अध्यक्ष ने कहा कि शराब और अपराध का गहरा संबंध् ा होता है। ये भाजपा राज में अपराध् ा के खिलाफ 'जीरो ट लरेंस' के 'जीरो' हो जाने का एक और उदाहरण बनेगा।

दोस्त का बर्थडे मना रहे युवक पर चाकू से हमला

लखनऊ। गोमतीनगर विस्तार इलाके में जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट पर दोस्त का बर्थडे मना रहे युवक पर करीब आधा दर्जन लोगों ने घेर कर हमला कर दिया। इस दौरान एक युवक ने चाकू से भी हमला करने का प्रयास किया। आसपास के लोगों के आने से हमलावर धमकी देते हुये भाग निकले। पीड़ित ने पुरानी रंजिश में हमला करने का आरोप लगाया है। गौतमपल्ली थाना अंतर्गत जियामऊ निवासी प्रतीक यादव पुत्र मनोज यादव ने बताया कि मंगलवार को एक दोस्त का बर्थ डे था। उसने पार्टी देने के लिए गोमतीनगर विस्तार इलाके के जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नंबर चार के समीप बुलाया था। प्रतीक ने बताया कि चार दोस्तों के साथ गेट के सामने एक दुकान के सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। इसी दौरान सात से आठ युवक पहुंचे और उसे व साथियों को घेर कर गाली गलौज करने लगे। प्रतीक ने बताया कि १३ दिसंबर को केंद्रीय विद्यालय में कक्षा १० में पढ़ने वाले उसके भाई श्रेष्ठ से कुछ छात्रों का विवाद हुआ था। मामला थाने तक पहुंचा था। जहां पर सुलह समझौता करा दिया गया था। उसी मामले की रंजिश में मंगलवार को आरोपी उसे लात घूसों से पीटने लगे। प्रतीक का आरोप है कि गेट के समीप का एक दुकानदार भी हमलावरों में शामिल हो गया। उसने चाकू से हमला करने का प्रयास किया। इसमें वह बालबाल बचा। आसपास के लोगों के आने पर हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुये भाग निकले। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर घटना से जुड़ा ५ सेकेंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में चाकू पकड़े युवक गाली गलौज करते दिख रहा है। युवक को एक लड़की पकड़ कर खींचते दिख रही है। इंस्पेक्टर गोमतीनगर विस्तार सुधीर अवस्थी ने बताया ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है और न ही इस संबंध में कोई तहरीर मिली है। मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जायेगी।

पत्नी ने किया चाय बनाने के इन्कार, पति ने तलवार से उड़ा दी गर्दन

गाजियाबाद। इन दिनों लोगों को गुस्सा काफी अधिक आने लगा है, जिसके बाद वो ऐसे कदम उठा लेते हैं कि इसपर पछतावा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। ऐसा ही एक कदम एक पति ने अपनी पत्नी के साथ उठाया है, वो भी सिर्फ चाय बनाने जैसे मामले पर लड़ाई होने के कारण गाजियाबाद के भोजपुर थाना इलाके में मंगलवार की सुबह एक हैरान करने वाली घटना हुई है जहां एक पति पत्नी के बीच सिर्फ चाय बनाने को विवाद हो गया। मगर ये विवाद इतना गंभीर हो गया कि इसमें पत्नी की हत्या हो गई। चाय बनाने पर हुई अनबन के बीच पति ने घर में रखी ध् ाारदार तलवार से पत्नी की गर्दन पर जोरदार वार किया। इस हमले में पत्नी की मौत हो गई है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति फरार हो गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस ने

शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इसके साथ ही फरार पति को ढूंढने में भी पुलिस की टीम जुट गई है। आरोपी पति की तलाश कर रही है। जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद के थाना भोजपुर थाना क्षेत्र स्थित फजलगढ़ गांव में मंगलवार की सुबह लगभग छह बजे धर्मवीर नाम के व्यक्ति ने अपनी ५० वर्षीय पत्नी सुंदरी को चाय बनाने को कहा। चाय बनाने को लेकर पति–पत्नी के बीच विवाद हो गया जो गंभीर रुप में बदल गया। दोनों के बीच चाय बनाने को लेकर बहस इतनी अधिक हुई की पति बेहद गुस्से में आ गया। पति ने घर में रखी ध् ाारदार तलवार निकाली और पत्नी की गर्दन पर पीछे से वार कर दिया। जब पति ने पत्नी को मारा तो वो चूल्हे पर चाय बना रही थी। इस हमले के बाद पत्नी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बता दें कि सुंदरी और धर्मवीर के पांच बच्चे हैं। घटना के समय सभी बच्चे सो रहे थे। वहीं पुलिस का कहना है कि घटना को अंजाम देने के बाद से ही आरोपी धर्मवीर फरार है। पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए टीमें लगाई है। आरोपी को जल्द ही हिरासत में लिया जाएगा।

'१५० सांसदों के निलंबन पर कोई चर्चा क्यों नहीं', मिमिक्री मामले बोले राहुल गांधी

नई दिल्ली। संसद परिसर में तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद द्वारा राज्यसभा के सभापति जगदीप ध् ानखड़ की नकल करने को लेकर विवाद के बीच, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि संबंध् ित विपक्षी सदस्य को सदन से ष्बाहर निकाल दिया गयाष् और वीडियो उनके निजी फोन पर रिकॉर्ड किया गया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसने अपमान किया और कैसे? सांसदों को बाहर निकाल दिया गया, मैंने वीडियो बनाया, लेकिन यह मेरे फोन पर है। मीडिया (क्लिप) दिखा रहा है। अपने बयान में राहुल ने कहा कि सांसद वहां बैठे थे, मैंने उनका वीडियो शूट किया। मेरा वीडियो मेरे फोन पर है। मीडिया इसे दिखा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी ने कुछ नहीं कहा। हमारे १५० सांसदों को (सदन से) बाहर निकाल दिया गया है लेकिन मीडिया में उस पर कोई चर्चा नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि अडानी पर कोई चर्चा नहीं, राफेल पर कोई चर्चा नहीं, बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं। हमारे सांसद निराश होकर बाहर बैठे हैं लेकिन आप उस (मिमिक्री) पर चर्चा कर रहे हैं। वहीं, उप–राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मिमिक्री की भी जिक्र किया और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आप संसद में नेताओं को वाद–विवाद के लिए भेजते हैं। लेकिन कल कुछ लोगों ने संसद में वाद–विवाद की जगह जोकर का, नकल करने का काम पकड़ लिया। कल एक सांसद भारत के उप–राष्ट्रपति की नकल संसद के प्रांगण में ही कर रहा था और कांग्रेस नेता राहुल गांधी उसकी वीडियो बना रहा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका इतिहास १०० वर्ष से भी पुराना है। उस कांग्रेस का नेता किसान पुत्र, जाट पुत्र और ओबीसी के प्रतिनिधि और

उप राष्ट्रपति के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की तौहीन कर रहा है। संसद की सुरक्षा में सेंध की घटना पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर हंगामा करने पर दोनों सदनों से ६० से अधिक विपक्षी सदस्यों को निलंबित किए जाने के विरोध में विपक्ष के सांसदों ने कल मंगलवार को संसद परिसर में प्रदर्शन किया और सदन की 'म क कार्यवाही' का आयोजन किया था। निलंबित सांसदों ने संसद के नए भवन के मकर द्वार पर धरना दिया। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्य कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, सदनों की कार्यवाही का संचालन किए जाने की नकल उतारी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधीबनर्जी द्वारा कार्यवाही के संचालन की नकल किए जाने का मोबाइल फोन से वीडियो बनाते देखे गए।

स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों को तैयार रहने को कहा, बैठक के बाद बोले- घबराने की जरूरत नहीं

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुधवार को कोविड–१९ के मामलों में वृद्धि के बीच देश के अस्पतालों को तैयार रहने को कहा। उन्होंने देश में कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान निगरानी और लोगों के साथ संचार बढ़ाने को भी कहा। उन्होंने कहा कि अब एक–दूसरे के साथ मिलकर काम करते हुए 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण के साथ मिलकर काम करने का समय आ गया है। हमें सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यह बैठक विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मामलों में वृद्धि के बीच जेएन.१ कोरोना वायरस स्ट्रेन को 'रुचि के प्रकार' के रूप में वर्गीकृत करने के बाद हुई है। इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी, गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी जैसी श्वसन संबंधी बीमारियों में हालिया वृद्धि को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने दिल्ली में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं की तैयारियों पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, भारती प्रवीण पवार, स्वास्थ्य सचिव सुधांश पंत, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव डॉ. राजीव बहल और नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वीके पॉल भी बैठक का हिस्सा थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, केरल में मंगलवार को कोविड–१९ के २९२ नए सक्रिय मामले और तीन मौतों की सूचना के बाद यह विकास हुआ। राज्य में सक्रिय मामलों की कुल संख्या बढ़कर २,०४१ हो गई। पिछले २४ घंटों में २२४ लोग कोविड–१९ से ठीक हुए, जिससे ठीक होने वालों की कुल संख्या ६८.३७ लाख हो गई। पिछले दिन की तुलना में ३४१ मामलों की वृद्धि के बाद बुधवार को भारत का सक्रिय केसलोएड बढ़कर २,३११ हो गया। पिछले दिन २७० लोगों के ठीक होने के बाद वायरस से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर ४,४४,७०,३४६ हो गई।

अनियंत्रित कार ने ट्रेलर को टक्कर मारी,महिला की मौत

प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिले के थाना कोहड़ौर के कोहड़ौर कस्बेमें मंगलवार को एक अनियंत्रित कार

ने पीछे से ट्रेलर को टक्कर मार दी जिससे कार सवार एक महिला की मौत हो गयी और उसका पति व बेटा घायल हो गये। पुलिस ने यह जानकारी दी। कोहड़ौर थाने के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) कमलेश पाण्डेय ने बताया कि क्षेत्र के अयोध्या–प्रयागराज राजमार्ग पर कोहड़ौर कस्बे में हुई इस घटना में शाहगंज सुलतानपुर के निवासी मनीष बरनवाल (४५) उनकी पत्नी विभा (४२) व बेटा अनिकेत (१७) गंभीर रूप से घायल हो गए। एसएचओ ने बताया कि तत्काल तीनों घायलों को मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि महिला के पति व बेटे की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हेंप्रयागराज के एसआरएन अस्पताल भेज दिया दिया गया। परिवार अपने रिश्तेदार के यहां भदोही जा रहा था। पाण्डेय ने बताया कि पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिए गए।

पत्नी के हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

गौतमबुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर की जिला अदालत ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में दोषी को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और १० हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता नितिन कुमार त्यागी ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रणविजय प्रताप सिंह की अदालत ने १० अप्रैल २०२१ को दर्ज इस मामले में आरोपी पति सोनू को सजा सुनाई है। त्यागी ने बताया कि मृतका के भाई जितेंद्र कुमार ने थाना सेक्टर–४६ में दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया था कि सर्फाबाद गांव निवासी उसके जीजा सोनू ने १० अप्रैल २०२१ दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी बहन पूनम की हत्या कर दी। शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस ने सोनू को गिरफ्तार कर लिया, जांच शुरू की और उसके खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ता और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद मामले में सोनू को दोषी पाते हुए, उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर १० हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

सड़क हादसे में किशोर की मौत, दो घायल

नोएडा। उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध जिले के ग्रेटर नोएडा में एक सड़क हादसे में एक किशोर की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गये। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना बीती रात कासना थाना क्षेत्र के सिरसा गोल चक्कर के पास की है। थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र शंकर पांडे ने बदायूं जिले के निवासी सत्येंद्र कुमार की शिकायत के हवाले से बताया कि उनकी पत्नी प्रीती, बेटा बलराज तथा सौरभ एक कार से हरियाणा के फरीदाबाद जिले से बदायूं जा रहे थे। उन्होंने बताया कि सिरसा गोल चक्कर के पास कार डिवाइडर से

टकराकर पलट गई और घायलों को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां सौरभ (१४) की मौत हो गई। थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत में कार चालक पर शराब पीकर तथालापरवाही से कार चलाने का आरोप लगाया गया है और मामला दर्ज कर लिया गया है।

नकली पेंटिंग बेचकर बैंकर से करीब १८ करोड़ रुपये ठगने के आरोप, मामला दर्ज

मुंबई। मुंबई में पुलिस ने एक निवेश बैंकर को नकली पेंटिंग बेचकर १७.६ करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक आर्ट डीलर और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बैंकर पुनीत भाटिया की शिकायत के आधार पर बताया कि आरोपियों ने यह कहकर पेंटिंग बेचीं थीं कि ये मनजीत बावा और फ्रांसिस न्यूटन सूजा जैसे जाने माने चित्रकारों की कलाकृतियां हैं, लेकिन बाद में उसे पता चला कि ये पेंटिंग उनकी नहीं है। एक अधिकारी ने बताया कि ताड़देव पुलिस ने वकील विश्वांग देसाई और आर्ट डीलर राजेश राजपाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं ४०६ (आपराधिक विश्वासघात), ४२० (धोखाधड़ी) और ४६७,४६८, ४७१ (जालसाजी से संबंधित अपराध) के तहत मामला दर्ज किया, लेकिन इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया।

१४१ सांसदों के निलंबन लोकतंत्र का गला घोंटा गया, हम डरेंगे नहीं : सोनिया गांधी

नई दिल्ली। संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र में विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर बुधवार को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में इसकी निंदा की गई। कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) प्रमुख सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने लोकतंत्र का गला घोंट दिया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव परिणाम पार्टी के लिए बेहद निराशाजनक रहे। सोनिया ने कहा कि भारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं लेकिन हमें विश्वास है कि हमारा धैर्य, हमें सफलता दिलाएगा। हमारी विचार धारा और मूल्य हमारे मार्गदर्शक हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ माह में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। पार्टी के और विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के सदस्य के तौर पर हमें कठिन परिश्रम करना है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि विविधता भारत की ताकत है, भाजपा ने एकता की इस भावना को योजनाबद्ध तरीके से कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि संसद के विपक्षी सदस्यों ने १३ दिसंबर

की असाधारण घटनाओं को संबोधित करते हुए लोकसभा में गृह मंत्री द्वारा दिया जाने वाला एक बयान मांगा था। इस अनुरोध के साथ जिस अहंकार के साथ व्यवहार किया गया उसका वर्णन करने के लिए शब्द नहीं हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस सत्र में जम्मू–कश्मीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू जैसे महान देशभक्तों को बदनाम करने के लिए इतिहास को विकृत करने और ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ने–मरोड़ने वाले लोग लगातार अभियान चला रहे हैं। सोनिया ने कहा कि इन प्रयासों में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने खुद मोर्चा संभाला है, लेकिन हम डरेंगे या झुकेंगे नहीं। हम सच बोलने पर कायम रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि महिला आरक्षण विधेयक को इस शर्त के साथ पारित किया जाना कि इसे केवल परिसीमन या जनगणना के बाद ही लागू किया जाएगा, महिलाओं को गुमराह करने और उनके वोट हासिल करने के इरादे से किया गया एक दिखावा है, जबकि उन्हें जो हक मिला है, उससे पीछे हटना है। संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लंबे समय से अपेक्षित है। बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि महिलाओं के लिए आरक्षण तुरंत लागू किया जाना चाहिए और इसमें ओबीसी समुदाय सहित सभी समुदायों की महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिए।

अदालतों में सुरक्षाकर्मियों के अलावा और कोई हथियार नहीं ले जा सकता : उच्च न्यायालय

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को कहा कि अदालत परिसर की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर, वकील, वादकारी या अन्य व्यक्ति राज्य के अदालत परिसरों में हथियार नहीं ले जा सकता। पीठ ने जिला न्यायाधीशों, अन्य न्यायिक अधिकारियों, अदालत परिसरों के सुरक्षा प्रभारियों व शस्त्र लाइसेंस प्राधिकारियों को ऐसे दोषी व्यक्तियों (अदालत परिसर में हथियार ले जाने वालों) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और लाइसेंस प्राधिकारी को उनके हथियार लाइसेंस रद्द करने के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ ने बाराबंकी के युवा वकील अमनदीप सिंह द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि अदालत परिसर, अधिवक्ता कक्षों, कैंटीन, बार एसोसिएशन या परिसर में किसी अन्य स्थान पर हथियार ले जाना सार्वजनिक शांति व सुरक्षा का उल्लंघन माना जाएगा। याचिका में याची का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने संबंधी आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि वह एक जूनियर अधिवक्ता है और तमाम विपक्षी पक्षकारों की नाराजगी की वजह से उसे जान का खतरा है। याचिका में कहा गया कि अपने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए शस्त्र रखना उसका मौलिक अधिकार है। राज्य सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि बाराबंकी कचहरी परिसर में शस्त्र लेकर जाने के कारण याची का लाइसेंस रद्द किया गया है। दरअसल, कानूनी प्रैक्टिस के लिए २०१८ में नामांकित किया गया याचिकाकर्ता बाराबंकी अदालत परिसर में लाइसेंसी हथियार लेकर गया था। इसके बाद उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई और बाद में जिला मजिस्ट्रेट ने उनका शस्त्र लाइसेंस भी रद्द कर दिया।

आईआईटी–कानपुर की शोध टीम की सदस्य ने की आत्महत्या

कानपुर। कानपुर में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) की शोध टीम की ३४ वर्षीय सदस्य ने मंगलवार को छात्रावास की दूसरी मंजिल के अपने कमरे में छत के पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान ओडिशा के कटक की रहने वाली पल्लवी चिल्का के रूप में हुई है।पुलिस ने बताया कि मामला तब सामने आया जब दोपहर में सफाई कर्मचारियों ने चिल्का का दरवाजा खटखटाया और कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। पुलिस के अनुसार सफाई कर्मचारी ने दोपहर में कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर झांकने पर उसे पंखे से लटका हुआ पाया, इसके बाद उसने अधिकारियों को सूचित किया। कल्याणपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) धनंजय पांडे ने पत्रकारों को बताया

कि आत्महत्या की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम तुरंत आईआईटी परिसर में पहुंचीं और मामले की जांच शुरू की। एसएचओ ने बताया कि पुलिस दरवाजा तोड़कर छात्रावास के कमरे में दाखिल हुई और शव को नीचे उतारा। पांडेय ने कहा कि प्रारंभिक जांच में आत्महत्या के पीछे अवसाद का कारण बताया गया है। उन्होंने कहा कि पीड़िता के परिजनों के आने के बाद बुधवार को शव का पोस्टमार्टम कराने का निर्णय लिया गया है। एसएचओ ने बताया कि पल्लवीतीन दिन पहले ही आरए छात्रावास में शिफ्ट हुई थीं। इससे पहले वह एक निजी किराये के मकान में रह रही थीं। संस्थान ने एक प्रेस बयान में पल्लवी के असामयिक और दुर्भाग्यपूर्ण निधन पर दुख व्यक्त किया। बयान में कहा गया है कि पल्लवी के निधन के साथ संस्थान ने एक प्रतिभाशाली और होनहार युवा शोधकर्ता खो दी।

वीएचपी ने आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को किया आमंत्रित

लखनऊ। विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के अध्यक्ष आलोक कुमार और वीएचपी के अन्य सदस्यों ने पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को २२ जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी को भी आमंत्रित किया गया था। यह बात राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा मीडिया को बताए जाने के तुरंत बाद आई है कि दिग्गजों से उनकी उम्र और कड़ाके की ठंड के कारण न आने का अनुरोध किया गया था। आडवाणी, अब ९६ वर्ष, और जोशी, ८९, ने राम जन्मभूमि आंदोलन का आगे बढ़कर नेतृत्व किया। पूर्व उप प्रधान मंत्री, आडवाणी ने आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने के लिए १९९० में गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक 'रथ यात्रा' निकाली। इस यात्रा के कारण उत्तर भारत के कई शहरों में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। दो साल बाद जब ६ दिसंबर १९९२ को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाई गई तो बीजेपी के दोनों दिग्गज मौके पर मौजूद थे। विहिप के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन के नेता आडवाणी और जोशी को २२ जनवरी के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है। वीएचपी के हैंडल एक्स पर एक पोस्ट के अनुसार, कुमार ने कहा, 'हमने रामजी के आंदोलन के बारे में बात की। दोनों वरिष्ठों ने कहा कि वे इस कार्यक्रम में आने की पूरी कोशिश करेंगे।' यह राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने दिग्गजों को दूर रहने के लिए कहा था। राय ने संवाददाताओं से कहा, ३दोनों परिवार के बुजुर्ग हैं और उनकी उम्र को देखते हुए उनसे न आने का अनुरोध किया गया था, जिसे दोनों ने स्वीकार कर लिया।३ उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। इस टिप्पणी से बड़ा विवाद खड़ा हो गया, कई लोगों ने भाजपा नेतृत्व पर एक समय पार्टी का नेतृत्व करने वाले अनुभवी नेताओं को दरकिनार करने और उनका अपमान करने का आरोप लगाया। राय ने कल कहा कि छह प्राचीन विद्यालयों के शंकराचार्यों, लगभग ४,००० संतों और २,२०० अन्य लोगों को भव्य समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसमें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। मेहमानों में काशी विश्वनाथ और वैष्णो देवी जैसे प्रमुख मंदिरों के प्रमुख शामिल होंगे।

यूपी की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रही योगी सरकार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रही योगी सरकार प्रदेश में विकास के सभी मानकों पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। ऐसे में, प्रदेश में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित मानकों के पालन के साथ ही सु ढ़ीकरण व नवीनीकरण प्रक्रिया को गति देने पर फोकस कर रही है। इस क्रम में, प्रदेश में हर घर जल जीवन मिशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को ग्राफिक मॉनिटर सिस्टम व एलईडी वीडियो वॉल सिस्टम समेत मॉडर्न इक्विप्मेंट्स से लैस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सीएम योगी के विजन के अनुसार, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने प्रक्रिया को शुरू करते हुए उपकरणों की स्थापना के लिए अनुभवी एजेंसियों की कार्य आवंटित किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इस क्रम में रिक्वेस्ट फ र प्रपोजल (आरएफपी) प्रक्रिया के जरिए आवेदन मांगे गए हैं। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के कार्यकारी निदेशक के देखरेख व दिशा–निर्देशन में इस प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा। प्रक्रिया के अनुसार, ई–निविदा के जरिए आवेदन प्रस्तुत करने वाली अनुभवी एजेंसियों को बिडिंग फ मेंट्स टेक्निकल व फाइनेंशियल को पूरा करना होगा। इनके जरिए, जिस एजेंसी का निर्धारण राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन में ग्राफिक म निटर सिस्टम व एलईडी वीडियो वॉल सिस्टम समेत म डर्न इक्विप्मेंट्स से लैस करने के लिए होगा उसे कई कार्यों को पूर्ण करना होगा। इसमें आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, संचालन, कमीशनिंग व स्टाफ को ट्रेनिंग देने जैसे कार्य प्रमुख हैं। इसके जरिए डेल्टा मेक ग्राफिक डिस्प्ले सिस्टम की आपूर्ति और स्थापना का भी मार्ग प्रशस्त होगा जो कई मायनों में विशिष्ट होगा। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा जिन आधुनिक प्रणालियों के विकास व उच्चीकरण प्रक्रिया को संस्थान में लागू किया जा रहा है उसमें वीडियो क न्फ्रेंस सिस्टम, एंप्लिफआयर, स्पीकर्स, लाउडस्पीकर्स, कॉम्पैक्स प्रेजेंटेशन स्विचर समेत कई उपकरण व गैजेट्स शुमार हैं। कुल ६ प्रकार के डिजिटल इक्विप्मेंट्स की खरीद को व्यापक स्तर पर पूर्ण किया जाएगा जिससे निगरानी प्रणाली को विकसित करने के साथ ही प्रचार–प्रसार के माध्यम को भी सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।

हमारे अन्य प्रतिनिधि
lat; ckt ibZ
lhrkiqj
eks-9935160370
प्रियंका त्रिपाठी
नई दिल्ली
विधिक सलाहकार
lqj'k ukjk;.k feJ
क्षेत्रीय सम्पादक
lkjHk dqekj] fcgkj
eks-09386075289
मो० अरशद
cgjkbp
eÅ

'सालार' को ए सर्टिफिकेट मिलने से नाखुश डायरेक्टर प्रशांत नील

मुंबई। प्रभास स्टारर फिल्म सालार रिलीज होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए है और इस फिल्म को लेकर फिल्म प्रशंसको की उत्सुकता काफी बढ़ गयी है, लेकिन फिल्म सालार के निदेशक प्रशांत नील ने फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिलने को लेकर निराशा व्यक्त की है और सेंसर बोर्ड के इस फैसले से वह नाखुश हैं। इस साल 'आदिपुरुष' जैसी फिल्म करने के बाद प्रभास बहुत जल्द फिल्म 'सालार' में नजर आने वाले हैं। प्रभास की आने वाली इस फिल्म को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। रिलीज से पहले 'सालार पार्ट–१ सीजफायर' को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंसर बोर्ड की तरफ से मिले ए सर्टिफिकेट को लेकर यह फिल्म सुर्खियों में है। इस बीच फिल्म के निदेशक प्रशांत नील ने इस मामले पर अपनी राय रखी है और सेंसर बोर्ड के फैसले पर निराशा व्यक्त की है। हाल ही में 'सालार' के प्रमोशन के दौरान प्रशांत ने 'बाहुबली' फेम निदेशक एस एस राजामौली के साथ एक खास बातचीत की है। इस दौरान 'केजीएफ चौप्टर २' के निर्देशक ने सालार फिल्म को मिले ए सर्टिफिकेट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, "सालार दो दोस्तों देवा और वर्धा की कहानी है। जिसमें नाटक और हिंसा भी देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जिससे सीबीएफसी की तरफ से ए सर्टिफिकेट दिया जाए। सेंसर बोर्ड ने फिल्म में से कुछ दृश्यों को काटा दिया फिर भी मैने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। मैंने कोई अश्लील फिल्म नहीं बनाई है जो इसे ए सर्टिफिकेट मिले।" 'सालार पार्ट–१ सीजफायर' का फिल्मी प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और २२ दिसंबर (शुक्रवार) को प्रभास की सालार बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। इस फिल्म के जरिए प्रभास की फिर से बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार वापसी के तौर पर देखा जा रहा है।

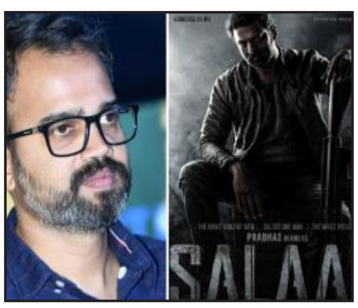

'डंकी' मेरी सर्वेश्रेष्ठ फिल्म, दर्शकों को मातृभूमि और परिवार से प्यार करना सिखाएगी' शाहरुख खान

दुबई। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान ने 'डंकी' को अपनी अबतक की 'सर्वश्रेष्ठ' फिल्म बताते हुए कहा कि यह दर्शकों को उनकी मातृभूमि और परिवार से प्यार करना सिखाएगी। फिल्म का निर्देशन राजकुमार हिरानी ने किया है और यह २१ दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह कॉमेडी फिल्म है और किसी देश में अवैध तरीके से घुसने की 'डंकी फ्लाइट' तरकीब पर आधारित है। अभिनेता ने कहा कि "डंकी" अपने देश को प्रेम करने के बारे में है। खान ने कहा, 'डंकी' मेरी सर्वश्रेष्ठ फिल्म है... यह फिल्म आपको अपनी मातृभूमि, माता–पिता से प्यार करना सिखाएगी।' उन्होंने यहां रविवार को फिल्म का प्रचार करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में कहा कि यह फिल्म विदेश जाने और अपने लिए भविष्य तलाशने को दिखाती है, लेकिन अपने घर से सबसे अधिक प्यार करना भी बताती है। अभिनेता ने कहा, "यह घर वापसी के बारे में है। आप दुनिया में कहीं भी रहें, लेकिन आप वापस अपनी मिट्टी की ओर आते हैं।" 'डंकी' खान की वर्ष २०२३ की तीसरी और आखिरी फिल्म है। इससे पहले उनकी 'पठान' और 'जवान' फिल्में आई थीं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की थी। खान (५८) ने कहा कि उन्होंने 'डंकी' अपने लिए बनाई है। उन्होंने कहा, "जब मैंने 'जवान' बनाई तो मैंने सोचा कि मैंने युवाओं के लिए एक फिल्म बनाई है लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं बनाया। फिर, मैंने 'डंकी' बनाई, यह फिल्म मेरे लिए है। यह मेरे दिल के बहुत करीब है।" उन्होंने कहा, "जब मैं 'पठान' कर रहा था, तो फिल्मों के बारे में लिखने वाले और शायद फिल्मों के निर्माताओं से ज्यादा जानने वाले कई लोगों ने कहा कि शाहरुख फिल्मों में किस तरह की भूमिकाएं निभा रहे हैं।" खान ने कहा, "मुझे हकीकत में लगा कि मुझे ऐसी फिल्में करनी चाहिए जिनका किरदार मेरे दिल से निकलता हो। आपने इस साल मेरी जो भी फिल्में देखीं उनका किरदार मैंने दिल से निभाया है। इस साल का अंत मैं अपने लिए की गई फिल्म से करना चाहता था। कृपया मेरे लिए २१ दिसंबर को 'डंकी' जरूर देखें। मुझे यकीन है कि आपको फिल्म में कुछ ऐसा मिलेगा जो आपके दिल को छू जाएगा और आपको हंसाएगा।' 'डंकी' में खान के साथ तापसी पन्नू, विक्की कौशल, बोमन ईरानी, विक्रम कोचर और अनिल ग्रोवर भी हैं।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय द्वारा सांई आफसेट प्रिन्टर्स, 40 वासुदेव भवन भातखण्डे संगीत महाविद्यालय के पीछे, कैसरबाग लखनऊ से छपवाकर एमआईजी 2/379 रश्मिखंड शारदानगर आशियाना लखनऊ उ0प्र0 से प्रकाशित।
आर.एन.आई UPHIN/2010/32566

सम्पादक
आरती पाण्डेय
मो.9415087228
9889745884. 9807059191. 9026560178
Email- adbhutsamachar @yahoo.in
adbhut_samachar @rediffmail.com

सभी विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।

समाचार पत्र में छपी समस्त प्रकार की खबरों एवं लेखों का स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। समाचार पत्र में छपी खबर एवं लेख पत्रकारों के अपने निजी विचार हैं। समाचार पत्र से जुड़े समस्त पत्रकारों के पद अवैतनिक हैं। और वह सब स्वतंत्र पत्रकार हैं। प्रकाशक/सम्पादक